



2026:AHC:39447

प्रतिवेद्य

सुरक्षित: 03.12.25

पारित: 23.2.26

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या-41127 वर्ष 2025

अन्य 11 सम्बद्ध वाद

नूरी और एक अन्य .. याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... प्रतिपक्षीगण

पक्षगण के लिए उपस्थिति

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए अधिवक्ता: अखिलेश कुमार यादव, श्लोक जायसवाल उदयभान सिंह

प्रतिपक्षी (ओं) के लिए अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं-81

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1 - समस्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्वेताश्व अग्रवाल, जो न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए, तथा उनकी सहायता कर रहे श्री यशराज वर्मा, श्री दिनकर लाल एवं श्री सिराजुद्दीन, विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार त्रिपाठी एवं श्री प्रभाष कुमार तिवारी, उनके साथ श्री योगेश कुमार, श्री प्रमित कुमार पाल, श्री सुरेश बाबू, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री विजय कुमार श्रीवास्तव तथा श्री फूलचन्द, विद्वान स्थायी अधिवक्ताओं को भी सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के लिए भी निर्देश दिया गया है।

3. इस न्यायालय में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं ने एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने का फैसला किया है और उनका दावा है कि उन्हें निजी प्रतिपक्षियों से जीवन के खतरे की आशंका है। उनके द्वारा संबंधित जिलों की पुलिस से संपर्क किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने इन रिट याचिकाओं को दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सभी रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि उनके जिले की पुलिस को निजी प्रतिपक्षियों के साथ-साथ निजी प्रतिपक्षियों के अन्य परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/सहयोगियों से याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

4. चूंकि सभी रिट याचिकाओं में शामिल विवाद समान है, इसलिए उनका निर्णय एक संयुक्त निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

5. इस न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण मुद्दे की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, श्री श्वेताश्व अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने ऊपर नामित विद्वान अधिवक्ता की सहायता से मामले पर बहस की।

6. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करता है कि शादी करनी है या नहीं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहना है। एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या अपने साथी के साथ रहने का अधिकार है। उन्हें विवाह से बाहर जीने का अधिकार है।

7. वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि विषम यौन संबंध के वयस्कों के बीच लिव-इन संबंध किसी भी अपराध के बराबर नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इन मामलों में, याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा किया है, ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, जो उनकी प्रार्थना के अनुसार सुरक्षा के साथ किसी भी संबंध में प्रवेश करने के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक कानूनी उम्र है।

8. दूसरी ओर, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अंतरधार्मिक जोड़े हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (इसके बाद "अधिनियम, 2021" के रूप में संदर्भित) की धारा 8 और 9 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। अधिनियम के 27.11.2020 को लागू होने के बावजूद धर्मांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का कार्य गैरकानूनी और अवैध है और अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के मद्देनजर इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं अस्पष्ट, काल्पनिक हैं और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को किसी भी समकालीन शिकायत द्वारा समर्थित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई वास्तविक और तत्काल खतरा नहीं है। पुलिस अधिकारियों के समक्ष कथित तौर पर भेजे गए आवेदन में किसी विशिष्ट समय, तारीख या घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। रक्षा करने के लिए राज्य के दायित्व केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया गया है और पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब कोई विश्वसनीय और तत्काल खतरा मौजूद हो।

9. अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए मामले कानून याचिकाकर्ताओं की सहायता के लिए नहीं आएंगे क्योंकि ये निर्णय 27.11.2020 को लागू हुए अधिनियम, 2021 की घोषणा से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे।

10. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा किरण रावत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह, लखनऊ एवं अन्य, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 323 में प्रतिवेदित है, के प्रकरण में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि मुस्लिम व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विधि के अनुसार लिव-इन संबंध में निवास नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा आशा देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रकरण में रिट-सी संख्या 18743 of 2020 में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया तथा याचिका का विरोध किया।



11. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता की सहमति से याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जा रहा है।

12. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे वयस्क हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इस विशेष तथ्य पर उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। यह न्यायालय 12 रिट याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें 7 लड़कियां मुस्लिम हैं और वे हिंदू लड़कों के साथ रह रही हैं, जबकि पांच लड़कियां हिंदू हैं और वे मुस्लिम लड़कों के साथ रह रही हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सभी याचिकाओं में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को एक-दूसरे से प्यार हो गया है और उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है, लेकिन निजी प्रतिपक्षी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत रिट याचिकाओं को दायर की दी।

13. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट-सी संख्या-27338 वर्ष 2023 में पारित रजिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जो एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

14. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि रजिया (उपरोक्त) के मामले में भी, पक्षकारों में से एक धर्म से मुस्लिम था और दूसरा पक्ष धर्म से हिंदू था और इसी स्थिति में, न्यायालय ने रजिया (उपरोक्त) के मामले में सुरक्षा प्रदान की है।

15. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों का विरोध करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने किरण रावत (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि एक मुस्लिम अपनी शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है।



16. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2006)5 एस.सी.सी. 475 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो वह जिसे चाहें उसके साथ रह सकता है और उसकी पसंद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लता सिंह (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक हिस्से को सुविधा और तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:

"17. जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है और जितनी जल्दी इसे नष्ट किया जाए उतना अच्छा है। वास्तव में, यह ऐसे समय में राष्ट्र को विभाजित कर रहा है जब हमें राष्ट्र के सामने चुनौतियों का एकजुट होना होगा। इसलिए, अंतरजातीय विवाह वास्तव में राष्ट्रीय हित में हैं क्योंकि वे जाति व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। हालांकि, देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि जो युवा पुरुष और महिलाएं अंतरजातीय विवाह से गुजरते हैं, उन्हें हिंसा की धमकी दी जाती है, या वास्तव में उन पर हिंसा की जाती है। हमारी राय में, हिंसा या धमकी या उत्पीड़न के ऐसे कार्य पूरी तरह से अवैध हैं और जो लोग उन्हें करते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह अपनी पसंद के किसी से भी शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं या उकसाते हैं और इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो एक वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, जो एक बालिग है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार आगे कड़ी कार्रवाई की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाती है। हम कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों की 'ऑनर' किलिंग के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, और वास्तव में वे क्रूर, सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्यों के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के इस तरह के कृत्यों को खत्म कर सकते हैं।

17. किसी ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करने के लिए, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए जिसे वह पसंद करता है, **शफीन जहां बनाम अशोकन केएम और अन्य (2018) 16 एस.सी.सी. 368** में रिपोर्ट किए गए अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भी भरोसा किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक वयस्क व्यक्ति की पसंद के अधिकार को उचित महत्व देने पर जोर दिया, जिसे संविधान एक वयस्क व्यक्ति को प्रदान करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। किसी भी धर्म, विश्वास, धर्म, जाति आदि का जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। न तो राज्य, न कानून, न ही समाज साथी की पसंद को निर्धारित कर सकता है। इस अधिकार को कानून के माध्यम से छोड़कर नहीं छीना जा सकता है जो पर्याप्त रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है। शफीन जहां (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"26. उम्मू सबीना बनाम केरल राज्य और अन्य, (2011)10 एस.सी.सी. 781 में, न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत को हमारे संवैधानिक कानून में और भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में शामिल किया गया है जहां न्यायाधीश एक लिखित संविधान के तहत कार्य करते हैं और जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का एक अध्याय है, न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करें, बल्कि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करें; और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके शक्ति का एक ही प्रयोग सबसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

27- इस प्रकार, उक्त रिट का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि कानून की मंजूरी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित न हो। यह देखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि उक्त अधिकार को किसी भी तरह से दूषित न किया जाए और किसी भी प्रकार की छल-कपट से इसकी पवित्रता प्रभावित न हो। न्यायालय की भूमिका यह देखना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए, उसकी स्वतंत्र पसंद के बारे में पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति को अवैध संयम से मुक्त किया जाए। जब हिरासत अवैध नहीं होगी तो मुद्दा अलग होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का गीत ईमानदारी के साथ गाया जाता है और किसी व्यक्ति की पसंद का सम्मान किया जाता है और संविधान की गारंटी के रूप में उसे सम्मानित दर्जा प्रदान किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत पसंद की अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, यदि उक्त विकल्प किसी वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। एक बार जब यह पहलू स्पष्ट हो जाता है, तो जांच और दृढ़ संकल्प को समाप्त करना होगा।

52. यहां यह बताना अनिवार्य है कि कानून के अनुसार पसंद की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पहचान की स्वीकृति है। उस अभिव्यक्ति में कटौती और उससे निकलने वाली अंतिम कार्रवाई समाज के प्रति प्रणाम के वैचारिक संरचनावाद पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिवादी इकाई को नष्ट कर देगी। सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है, लेकिन वे संवैधानिक रूप से प्रदत्त स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं। उक्त स्वतंत्रता एक संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों है। उस स्वतंत्रता से वंचित करना जो विश्वास की दलील पर पसंद में निहित है, अस्वीकार्य है। किसी व्यक्ति का उसके सार्थक अस्तित्व के प्रति आंतरिक विश्वास की स्वतंत्रता होना उसकी स्वायत्तता के लिए आवश्यक है; और यह संविधान के मूल मानदंडों को मजबूत करता है। विश्वास चुनना व्यक्तित्व का आधार है और इसके बिना, पसंद का अधिकार एक छाया बन जाता है। यह याद रखना होगा कि अधिकार की प्राप्ति अधिकार प्रदान करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह का वास्तविकीकरण वास्तव में किसी भी प्रकार की सामाजिक कुख्याति को बहिष्कृत करता है और पितृसत्तात्मक वर्चस्व को दूर रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिवादी विश्वास और पसंद की अभिव्यक्ति अधिकार के फलीभूत होने के लिए मौलिक है। इस प्रकार, हम इसे अपरिहार्य प्रारंभिक शर्त कहना चाहेंगे।



53 . उसकी पसंद को स्वीकार न करने का मतलब केवल एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकार के लिए असुविधा पैदा करना होगा जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ऐसी स्थिति की कल्पना दूर से नहीं की जा सकती। न्यायालय का कर्तव्य अधिकार को बनाए रखना है और अधिकार के दायरे को कम नहीं करना है जब तक कि कानून का वैध अधिकार न हो। वैध मंजूरी के बिना, स्वतंत्रता के केन्द्राकरण मूल्य को किसी व्यक्ति को अपनी पटकथा लिखने की अनुमति देनी चाहिए। व्यक्तिगत हस्ताक्षर अवधारणा का प्रतीक चिन्ह है।

54. मामले में, पिता अपने स्वयं के रुख और धारणा में महसूस कर सकता है कि उसकी बेटी के हितों की रक्षा करने के लिए उसके अधिकार का भारी उल्लंघन हुआ है, लेकिन उसके दृष्टिकोण या स्थिति को उसकी बेटी के मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने अपनी इच्छा से अपीलकर्ता से शादी की थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता और प्रतिपक्षी संख्या-9 के बीच विवाह को रद्द करने का बोझ अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से गलती की है, जब दोनों विवाह की अपनी प्रतिज्ञा के लिए खड़े थे।

18. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता नंदकुमा और एक अन्य बनाम केरल राज्य (2018) 16 एस.सी.सी. 620 के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया कि लिव इन रिलेशनशिप को अब विधायिका द्वारा ही मान्यता दी गई है और इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना स्थान मिल गया है।

19. कामिनी देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट सी संख्या-11108 वर्ष 2020 के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भी भरोसा किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है और याचिकाकर्ता, यदि वे वयस्क हैं, कानूनी रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के हकदार हैं।

20. उत्तर में, राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता / एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) ने भरोसा किया है, हालांकि एक ही धर्म के भीतर विवाह करते समय एक वयस्क व्यक्ति की पसंद का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, हालांकि, ये निर्णय अधिनियम के प्रख्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं की सहायता



के लिए नहीं आएंगे, 2021, जो 27.11.2020 को लागू हुआ। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा किया गया था, वे अधिनियम, 2021 की घोषणा से पहले पारित किए गए थे और किसी भी निर्णय में अधिनियम वर्ष 2021 पर विचार नहीं किया गया था।

21. राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अधिनियम, 2021 के अनुसार, अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के अलावा कोई व्यक्ति दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता है। प्रस्तुत मामलों में, किसी भी याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के तहत आवेदन दायर किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन को उनके द्वारा पसंद किया गया था। इसलिए, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और गलत काम करने वाले को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

22. खंडन में, वरिष्ठ अधिवक्ता /एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता केवल एक रिश्ते में रह रहे हैं और इस तरह, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 का अनुपालन आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करने का इरादा रखता है, तभी वह अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के अनुसार एक घोषणा देगा।

23. उपरोक्त तर्क का उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया और उन्होंने अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 का उल्लेख किया और कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के उद्देश्य से, अधिनियम, 2021 लागू होगा और जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे उस अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है दस साल तक और जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 का संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नानुसार हैं:

"धारा 3. गलत बयानी करके, बलप्रयोग, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती,

प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रतिषेध।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गलत बयानी के प्रयोग या अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष या अन्यथा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह के धर्मांतरण को उकसाने, समझाने या साजिश रचने की अनुमति नहीं देगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, इस उप-धारा में उल्लिखित कारकों के कारण विवाह या विवाह की प्रकृति में संबंध के अनुष्ठान द्वारा रूपांतरण को शामिल माना जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपने तत्काल पूर्व धर्म में पुनः परिवर्तित हो जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन धर्मांतरण नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तत्काल पूर्व धर्म का अर्थ है वह धर्म जिसमें व्यक्ति की आस्था, विश्वास था या व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया गया था।

धारा 5. धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा: (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह जुर्माने से भी भागी होगा जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा:

परन्तु जो कोई भी अवयस्क, विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, सोमन या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकती है और वह जुर्माने से भी भागी होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि जो कोई भी धर्म के सामूहिक परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह



जुर्माने से भी भागी होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा।

(2) जो कोई भी विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, वह उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक होगी और वह जुर्माने से भी भागी होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(3) जहां कहीं भी धर्मांतरण करने के इरादे से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, उस पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है या विवाह करने का वादा करता है या उसके लिए षड्यंत्र करता है, या किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बहलाकर या अन्यथा बेचकर उसका व्यापार करता है, या इस संबंध में प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है, एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष जन्म के लिए कारावास होगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:

बशर्ते कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

(4) न्यायालय उक्त धर्मांतरण के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा देय उचित मुआवजे का भी अनुमोदन करेगा, जो जुर्माने के अतिरिक्त पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

(5) जो को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषी ठहराया गया है, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिए, इस अधिनियम के तहत उस निमित्त उपबंधित दंड के दोगुने से अधिक नहीं की सजा का भागी होगा।

24. उपरोक्त प्रावधान का हवाला देते हुए, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने आगे कहा कि अधिनियम, 2021 की धारा 3 की व्याख्या से पता चलता है कि धर्मांतरण न केवल विवाह के



उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति में सभी संबंधों में भी आवश्यक है, इसलिए, अधिनियम, 2021, विवाह की प्रकृति में संबंध या लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने पर भी लागू होगा। किसी भी याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार धर्मांतरण के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में याचिकाकर्ताओं के संबंधों की रक्षा नहीं की जा सकती है। विवाह जैसे संबंध में याचिकाकर्ताओं के ऐसे रहने को न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

25. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

26. किरण रावत (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि मुस्लिम कानून में विवाह के बाहर यौन संबंध को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है। किरण रावत (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर-21 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"21. हालांकि, मुस्लिम कानून में विवाह के बाहर यौन संबंध को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है। "ज़िना" जिसे पति और पत्नी के बीच किसी भी यौन संभोग के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें विवाहेतर यौन संबंध और विवाहपूर्व यौन संबंध दोनों शामिल हैं और अक्सर अंग्रेजी में व्यभिचार के रूप में अनुवाद किया जाता है। इस्लाम में इस तरह के विवाह पूर्व यौन संबंध की अनुमति नहीं है। वास्तव में कोई भी यौन, कामुक, स्नेही कार्य जैसे कि चुंबन, छूना, घूरना आदि शादी से पहले इस्लाम में "हराम" हैं क्योंकि इन्हें "ज़िना" का हिस्सा माना जाता है जो वास्तविक "ज़िना" का कारण बन सकता है। कुरान (अध्याय 24) के अनुसार इस तरह के अपराध के लिए सजा अविवाहित पुरुष और महिला के लिए सौ कोड़े है जो व्यभिचार करते हैं, साथ ही विवाहित पुरुष और महिला के लिए "सुन्नत" द्वारा निर्धारित सजा के साथ जो पत्थर मारकर मार डाला जाता है।"

27. किरण रावत (उपरोक्त) के फैसले के संदर्भ में, भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम में किसी पुरुष या महिला को कोड़े मारकर या पत्थर मारकर मौत की सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, किसी व्यक्ति को मुस्लिम कानून/इस्लाम के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि किरण रावत के (उपरोक्त) फैसले में उद्धृत किया गया है।

28. इस न्यायालय की राय में, अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत अपराध को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आकर्षित करने के लिए, एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण आवश्यक है और यह कि धर्मांतरण गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह या विवाह की प्रकृति में संबंध के अभ्यास से होना चाहिए। धारा 3 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। "धर्मांतरण" को अधिनियम, 2021 की धारा 2(c) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"2 (सी)। धर्मांतरण" का अर्थ है अपने धर्म को त्यागना और दूसरे धर्म को अपनाना।

29. मामलों के वर्तमान समूह में, किसी भी याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया कि किसी भी तरह से, अन्य याचिकाकर्ता द्वारा अपने धर्म के परिवर्तन के लिए कोई प्रयास किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल यह दावा किया गया है कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अधिनियम, 2021 की धारा 4, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित प्राथमिकी/शिकायत दर्ज करने की शक्ति देती है। इन मामलों में, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है कि एक याचिकाकर्ता का धर्म परिवर्तित किया गया था या धर्मांतरण का प्रयास किया गया था। इसलिए, इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम, 2021 के प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था और उनके द्वारा दंडनीय अपराध किया गया था।

30. यहां तक कि अंतरधार्मिक विवाह भी अधिनियम, 2021 के तहत निषिद्ध नहीं है। अधिनियम, 2021 के तहत भी प्रावधान किया गया है, और जिसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना/परिवर्तित करना चाहता है, तो उससे अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन किसी को शादी के प्रयोजनों के लिए या लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तैयार संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"धारा 8. धर्म परिवर्तन से पूर्व घोषणा और धर्मांतरण के बारे में पूर्व-रिपोर्ट (1) जो

कोई भी अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है, वह जिला मजिस्ट्रेट या जिला



मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम साठ दिन पहले अनुसूची-I में निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा देगा कि वह अपने धर्म को स्वयं और अपनी स्वतंत्र सहमति से और बिना किसी बल जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के परिवर्तित करना चाहता है।

(2) धर्मान्तरक, जो एक धर्म के किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए धर्मांतरण समारोह करता है, ऐसे परिवर्तन की अनुसूची-II में विहित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी को, जो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं है, जहां ऐसा समारोह किया जाना प्रस्तावित है, को एक माह की अग्रिम सूचना देनी होगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) और (2) के तहत सूचना प्राप्त करने के बाद, प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के वास्तविक इरादे, उद्देश्य और कारण के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच करवाएगा।

(4) उप-धारा (1) और/या उप-धारा (2) के उल्लंघन से प्रस्तावित रूपांतरण को अवैध और शून्य घोषित करने का प्रभाव होगा।

(5) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह उस अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह महीने से कम नहीं होगा बल्कि तीन वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा बल्कि पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से भी भागी होगा जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

धारा 9. धर्म परिवर्तन के बाद की घोषणा (1) धर्मांतरित व्यक्ति धर्मांतरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर अनुसूची-III में निर्धारित प्रपत्र में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा भेजेगा जिसमें परिवर्तित व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट घोषणा की एक प्रति पुष्टिकरण की तारीख तक कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।



(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्, धर्मांतरण का विवरण जैसे जन्म तिथि, स्थायी पता, और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, वह धर्म जिससे धर्मांतरित मूल रूप से संबंधित था और जिस धर्म में उसने धर्मांतरण किया है, धर्मांतरण की तारीख और स्थान और धर्मांतरण के लिए की गई प्रक्रिया की प्रकृति इत्यादि।

(4) परिवर्तित व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित करने और घोषणा की विषय-वस्तु की पुष्टि करने के लिए घोषणा भेजने/दाखिल करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में घोषणा और पुष्टिकरण के तथ्य को दर्ज करेगा। यदि किसी भी आपति को अधिसूचित किया जाता है, तो वह बस उन्हें अभिलेखों कर सकता है, अर्थात्, आपत्तिकर्ताओं का नाम और विवरण और आपति की प्रकृति।

(6) घोषणा, पुष्टि और रजिस्टर से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां उन पक्षगण को प्रस्तुत की जाएंगी, जिन्होंने उनके अनुरोध पर अपने अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को घोषणा दी थी।

(7) उप-धारा 1 से 4 के उल्लंघन से उक्त रूपांतरण को अवैध और शून्य घोषित करने का प्रभाव पड़ेगा।

31. यह न्यायालय यहां याचिकाकर्ताओं को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखता है, बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में देखता है जो अपनी मर्जी और पसंद से काफी समय तक शांति और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। न्यायालयों और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप, दो व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार में एक गंभीर अतिक्रमण का गठन करेगा। यह न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि यदि कानून एक ही लिंग के दो व्यक्तियों को भी शांति से एक साथ रहने की अनुमति देता है, तो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न तो कोई व्यक्ति, न ही एक परिवार, और यहां तक कि राज्य को दो वयस्क व्यक्तियों के विषमलैंगिक संबंधों पर आपत्ति हो सकती है, जो अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। किसी व्यक्ति का निर्णय जो वयस्कता की आयु का है, अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ रहना पूरी तरह से एक व्यक्ति का अधिकार है और जब इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा क्योंकि इसमें पसंद की स्वतंत्रता, साथी चुनने का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

32. सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस, (2018) 2 एस.सी.सी. 197 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले से निपटा जहां अपीलकर्ता और प्रतिपक्षी की बेटी, जो एक वयस्क थी, ने कुवैत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जहां वह अपने पिता के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

9. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुवैत वापस जाने का इरादा रखती हैं। ऐसी स्थिति में, हमारी सुविचारित राय है कि एक वयस्क के रूप में, वह अपनी पसंद और स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हकदार है और न्यायालय इस पहलू में नहीं जा सकता है कि उसे पिता द्वारा मजबूर किया गया है या नहीं। कुवैत में अपने पिता के पास वापस जाने के लिए उसकी ओर से पर्याप्त कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसके कारणों से चिंतित नहीं हैं। उसने न्यायालय के समक्ष जो कहा है, वह अकेले मायने रखता है और यही इस न्यायालय के तर्क का मूल है, जो सभी विवादों को दूर रखता है।

10. यह कहने के लिए किसी विशेष जोर की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करने का अपना महत्व है। वह अपनी पसंद बनाने का हकदार है। अदालतें, जब तक विकल्प बनी रहती हैं, तब तक पैरेंट्स पैट्रिया की भूमिका नहीं निभा सकतीं। कानून की अनुमति के अनुसार बेटी अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने की हकदार है और अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होने वाले सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हम बिना किसी आपत्ति के ऐसा कहते हैं।



33. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है।

34. शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) 7 एस.सी.सी.192 में सर्वोच्च न्यायालय ने "ऑनर किलिंग" के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की, जिसे न्यायालय ने न केवल भयानक और बर्बर पाया, बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार और किसी व्यक्ति की गरिमा में भी हस्तक्षेप किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

44. स्वतंत्रता की अवधारणा को संवैधानिक संवेदनशीलता, सुरक्षा और इसके लिए खड़े मूल्यों की कसौटी पर तौला और परखा जाना चाहिए। यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उत्साहपूर्वक रक्षा करे क्योंकि किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व का स्वतंत्रता के साथ एक अविभाज्य संबंध है। स्वतंत्रता के निर्वाह के बिना, कानून के संवैधानिक रूप से वैध प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति का जीवन जीवित मृतकों के बराबर है, जिसे बिना विरोध के क्रूरता और यातना सहना पड़ता है और असहमति या असहमति दर्ज करने के लिए आवाज के बिना विचारों को थोपने को सहन करना पड़ता है। गरिमापूर्ण अस्तित्व की मूलभूत विशेषता उस गरिमा के लिए जोर देना है जिसमें दिव्यता की चिंगारी है और किसी भी प्रकार की अधीनता के बिना कानून के मापदंडों के भीतर पसंद की प्राप्ति है। स्वतंत्रता के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत गरिमा और पसंद की अवधारणाओं पर जोर देने का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। हम स्पष्ट रूप से और जोरदार ढंग से कह सकते हैं कि जीवन और स्वतंत्रता बिना गरिमा और पसंद एक ऐसी घटना है जो खोखलेपन को किसी व्यक्ति की पहचान की संवैधानिक मान्यता में प्रवेश करने की अनुमति देती है। (बल वर्धित)

45. किसी व्यक्ति का चुनाव गरिमा का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि जहां पसंद का क्षरण होता है, वहां गरिमा के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। यह सच है, यह संवैधानिक सीमा के सिद्धांत से बंधा हुआ है, लेकिन ऐसी सीमा के अभाव में, हमारा मतलब है, किसी को भी उक्त विकल्प के फलीभूत होने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अपनी पसंद को व्यक्त करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसकी पवित्र पूर्णता में गरिमा के बारे में सोचना बेहद मुश्किल होगा। जब दो वयस्क अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तो वे अपना रास्ता चुनते हैं; वे अपने रिश्ते को



पूरा करते हैं; उन्हें लगता है कि यह उनका लक्ष्य है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके पास अधिकार है और उक्त अधिकार का कोई भी उल्लंघन संवैधानिक उल्लंघन है।"

35. जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना साथी चुनने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निहित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। **केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एस.सी.सी.1** में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया: -

298. व्यक्ति की गोपनीयता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। गरिमा का आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा अपने आप में एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है। इसके सहायक पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। गोपनीयता के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य की प्राप्ति को सक्षम बनाती है। लिबर्टी का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक सबसेट है। गोपनीयता में सभी स्वतंत्रताओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर भी दूसरों को केवल एक निजी स्थान के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। गोपनीयता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन के लिए चिंता के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया है। लेकिन यह इसे प्रदान किए गए संवैधानिक संरक्षण से अलग नहीं होता है, एक बार गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझा जाता है जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रता के स्पेक्ट्रम में निहित है। समानता की गारंटी मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान की स्थिति द्वारा विनाश, चाहे वह शरीर का हो या मन का, मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है। शरीर की गोपनीयता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के



ठोस पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है। किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उस पर विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की गोपनीयता यह निर्धारित करने के लिए एक अनुल्लंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा। एक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा रूप चुप रहना है। मौन गोपनीयता के दायरे को दर्शाता है। एक कलाकार एक रचनात्मक प्रयास में आत्मा का प्रतिबिंब पाता है। एक लेखक विचार की प्रक्रिया के परिणाम को व्यक्त करता है। एक संगीतकार उन नोटों पर विचार करता है जो संगीत की दृष्टि से मौन की ओर ले जाते हैं। चुप्पी, जो भीतर है, यह चुनने की क्षमता को दर्शाता है कि विचारों और विचारों को कैसे व्यक्त किया जाए या दूसरों के साथ बातचीत कैसे की जाए। ये व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति को अपनी दायर कीओं पर निर्णय लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ें, स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है, जिसमें कोई क्या और कैसे खाएगा, जिस तरह से कोई कपड़े पहनेगा, जिस विश्वास का समर्थन करेगा और असंख्य अन्य मामले जिन पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए मन की गोपनीयता के भीतर एक विकल्प बनाने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है। ये उस तरीके के कुछ उदाहरण हैं जिसमें गोपनीयता स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करती है और स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आंतरिक है। संविधान में कोई अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें यह बताता है कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। न ही हमने भाग III के प्रावधानों को गोपनीयता के अल्फा प्रत्यय अधिकार के साथ टैग किया है: यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है। गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों



जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अविभाज्य मूल्यों के भीतर रहते हैं, जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। गोपनीयता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है। (बल वर्धित)

299. गोपनीयता मानव व्यक्तित्व के मूल का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक व्यक्ति की विकल्प चुनने और अंतरंग और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले निर्णय लेने की क्षमता को पहचानती है। फिर भी, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि व्यक्ति समुदायों में रहते हैं और समुदायों में काम करते हैं। उनके व्यक्तित्व प्रभावित करते हैं और बदले में उनके सामाजिक वातावरण द्वारा आकार दिए जाते हैं। व्यक्ति साधु नहीं है। व्यक्तियों का जीवन उतना ही सामाजिक घटना है। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में, व्यक्ति लगातार व्यवहार पैटर्न और समाज के बाकी हिस्सों पर प्रभाव डालने वाले रिश्तों में लगे रहते हैं। समान रूप से, व्यक्ति के जीवन को समुदाय में रहने से आत्मसात किए गए सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों द्वारा लगातार आकार दिया जा रहा है। (बल वर्धित)

323. गोपनीयता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास शामिल हैं। गोपनीयता अकेले रहने के अधिकार को भी दर्शाती है। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और व्यक्ति की अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है। जीवन के तरीके को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विकल्प गोपनीयता के लिए आंतरिक हैं। गोपनीयता विविधता की रक्षा करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को पहचानती है। जबकि गोपनीयता की वैध अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र और निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता केवल इसलिए खो या आत्मसमर्पण नहीं की जाती है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ी होती है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है; (बल वर्धित)

36. एक व्यक्ति को बहुमत प्राप्त करने पर वैधानिक रूप से एक साथी चुनने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जो न केवल उसके मानव अधिकार को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। मैं ऐसा इस कारण से कह रहा हूँ कि धर्मांतरण के प्रभाव के बावजूद, केवल इस तथ्य के बावजूद कि युगल एक साथ रह रहे थे, कथित संबंध को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विवाह से उत्पन्न होने वाले संबंध से अलग विवाह की प्रकृति में एक संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2005. किसी ऐसे व्यक्ति की पसंद की अवहेलना करना जो वयस्कता की आयु का है, न केवल एक वयस्क व्यक्ति की पसंद की स्वतंत्रता के विपरीत होगा, बल्कि विविधता में एकता की अवधारणा के लिए भी खतरा होगा।

37. इससे पहले, बेबी आलिया (नाबालिग) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ, रिट-सी संख्या-6408 वर्ष 2025 ने दिनांक 08.04.2025 के आदेश के माध्यम से इंटरफेथ लिव-इन कपल को सुरक्षा प्रदान की थी। बेबी आलिया (उपरोक्त) के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"5. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका है, जो अपने जैविक माता-पिता के माध्यम से, एक बच्चा है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के पिता और माता अलग-अलग धर्म के हैं और 2018 से एक साथ रह रहे हैं। बच्चा फिलहाल एक साल और चार महीने का है। बच्चे के माता-पिता निजी प्रतिपक्षीगण से कुछ खतरों से आशंकित हैं जो जैविक मां के कानूनों में पूर्ववर्ती हैं।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्व पति की मृत्यु के बाद, जैविक मां ने जैविक पिता के साथ रहना शुरू कर दिया।

8. हमारे विचार में, संवैधानिक योजना के तहत, माता-पिता, जो बड़े हैं, एक साथ रहने के हकदार हैं, भले ही उन्होंने शादी नहीं की हो (देखें: ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य (1976) 3 एस.सी.सी. 234 में रिपोर्ट किए गए; (क) क्या यह सच है कि लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य मामले (2006) 5 एस.सी.सी. 475 में दर्ज किए गए थे; और भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2011) 6 एस.सी.सी. 396)।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. बच्चे के माता-पिता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस अधिकारी निजी प्रतिपक्षियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के इच्छुक नहीं हैं और पुलिस अधिकारी बार-बार उन्हें अपमानित कर रहे हैं जब वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना से संपर्क करते हैं।

10 उसी के आलोक में, पुलिस अधीक्षक, संभल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि यदि बच्चे के माता-पिता थाना में आते हैं, तो प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट थाना चंदौसी, जिला संभल में दर्ज की जाए। संभल के पुलिस अधीक्षक को इस पहलू पर गौर करने का भी निर्देश दिया जाता है कि क्या कानून के अनुसार बच्चे और माता-पिता को कोई सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। अधिकारियों को ऊपर बताए गए निर्णयों के अनुसार कार्य करने का भी निर्देश दिया जाता है।

11. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

38. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोहम्मद शाहनूर मंसूरी बनाम दिल्ली राज्य के मामले में पुलिस आयुक्त और अन्य के माध्यम से, डब्ल्यूपी (क्रि।) संख्या-2305 वर्ष 2025, 08.08.2025 को निर्णय लिया है, ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की है। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"6. संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, एक गारंटी जिसे न्यायिक रूप से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में राज्य की भूमिका न तो निष्क्रिय है और न ही विवेकाधीन; यह अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व रखता है, भले ही उनके अपने परिवारों की इच्छाओं के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा की मांग की जाती हो।

8. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वयस्कों को अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सहमति देने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मूलभूत पहलू है। उस अधिकार को भय, जबरदस्ती या सामाजिक अस्वीकृति से भ्रामक नहीं बनाया जा सकता है। यह इस प्रकार है कि राज्य की



सुरक्षात्मक मशीनरी को तुरंत और प्रभावी ढंग से सक्रिय किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक वयस्क नागरिक की पसंद, स्वतंत्र रूप से और कानून की सीमा के भीतर, सार में संरक्षित है, न कि केवल रूप में।

9. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

राज्य याचिकाकर्ता और सुश्री को निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? जब तक वे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी नहीं कर लेते।

याचिकाकर्ताओं को तब तक सुरक्षित घर में रखा जाएगा जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक समझा जाए। खतरे की धारणा का आकलन संबंधित डीसीपी द्वारा समय-समय पर और सार्थक रूप से किया जाएगा, शक्ति वाहिनी (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों और निवारक उपायों को ध्यान में रखते हुए।

किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी जबरदस्ती, डराने या धमकी देने वाले कार्य की स्थिति में, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, जिसमें सुश्री के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ऐसी घटना, पुलिस को सूचित किए जाने पर, डीडी में तुरंत दर्ज की जाएगी, और कानून के अनुसार उचित निवारक और दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। पुलिस याचिकाकर्ताओं को की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित भी करेगी, ताकि सुरक्षात्मक प्रक्रिया में उनका विश्वास सुनिश्चित हो सके।

10. अलग होने से पहले, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी प्रत्येक वयस्क नागरिक को भय, जबरदस्ती या गैरकानूनी संयम से मुक्त होकर अपने स्वयं के जीवन की दिशा को आकार देने में सक्षम बनाती है। शादी करने का विकल्प, विशेष रूप से विश्वास की रेखाओं में, सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक अपेक्षाओं के लचीलेपन का परीक्षण कर सकता है, फिर भी कानून में, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का मामला बना हुआ है, जो



किसी भी बाहरी वीटो से प्रतिरक्षित है। जबकि माता-पिता की पीड़ा समझ में आती है, यह एक वयस्क के अपने जीवन साथी का चयन करने के अधिकारों को ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए, राज्य की भूमिका नुकसान से निष्क्रिय परिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के निर्माण तक फैली हुई है जिनमें ऐसे अधिकारों का सुरक्षित और सार्थक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यहां जारी किए गए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह स्वतंत्रता वास्तविक और संरक्षित दोनों बनी रहे।

39. इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 5823 के मामले में अंतर-जातीय और अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कानून पर चर्चा की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि अंतरधार्मिक संबंधों में जोड़े ऐतिहासिक रूप से अपने संघों को संपन्न करते समय उस भारी कठिनाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है और संघर्ष करना जारी रखा है। यह भी देखा गया कि संविधान में व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से पहले दूसरों को उनके प्रयोग की वैधता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रियो (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"116. औपनिवेशिक युग में अंतर-जातीय और अंतरधार्मिक विवाह असामान्य थे और स्थापित रीति-रिवाज या प्रथाएं ऐसे विवाहों को नियंत्रित नहीं करती थीं। तब, अब की तरह, समाज ने अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वालों को भेदभाव और उदारता के अधीन कर दिया। शुरू में ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं था जो इस तरह के विवाहों को नियंत्रित करता हो। विशेष विवाह अधिनियम 1872 को व्यक्तिगत कानून से स्वतंत्र विवाह संपन्न करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यदि अलग-अलग धर्मों के दो लोग शादी करना चाहते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को अपने धर्म का त्याग करना होगा ताकि वे अपने धर्म के समर्थक दर्शन का लाभ उठा सकें। उस समय के कानून ने एक रूपरेखा प्रदान नहीं की थी जिसके संदर्भ में विभिन्न धर्मों से संबंधित दो व्यक्ति अपने-अपने धर्मों के साथ अपने जुड़ाव या आध्यात्मिक संबंध को बनाए रख सकते थे और फिर भी एक दूसरे से शादी कर सकते थे।

117. संसद विशेष विवाह अधिनियम 1872 के सीमित और प्रतिबंधात्मक चरित्र के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रति सचेत थी और 1954 में एस.एम.ए. को अधिनियमित किया, जो एक अधिक अनुमेय कानून था जिसमें कोई भी दो व्यक्ति अपने संबंधित धर्मों को अस्वीकार किए बिना शादी कर सकते थे। यह निर्धारित करके कि "इस अधिनियम के तहत किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाह संपन्न किया जा सकता है," एस.एम.ए. ने अंतर-जातीय विवाहों को व्यक्तिगत कानून से स्वतंत्र करने के लिए एक तंत्र भी निर्धारित किया।

118. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के परिवार या रिश्तेदार अक्सर उन पर हिंसा करते थे, यहां तक कि उनकी बेरहमी से हत्या करने की सीमा तक भी। उनके समुदाय या तो इन अत्याचारों को नियुक्त करेंगे या उनमें भाग लेंगे। इस तरह की हत्याओं को बोलचाल की भाषा में "ऑनर किलिंग" के रूप में संदर्भित किया जाता है और अधिक सटीक रूप से जाति-आधारित हत्याओं के रूप में कहा जाता है। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि हिंसा की यह संस्कृति आज भी कायम है। अंतरजातीय और अंतर-विरोध में जोड़ों के खिलाफ इस हिंसा का सामना करने वाले दंपतियों ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने परिवारों और उनके संबंधों का विरोध करने वाले अन्य लोगों से सुरक्षा की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस न्यायालय को इस संदर्भ में हिंसा से उत्पन्न होने वाले मामलों पर रोक लगा दी गई है। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के इस न्यायालय ने अंतर-फेथ विवाहों पर ध्यान दिया। पीठ ने राज्य मशीनरी को निर्देश दिया कि वह ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करे जो शादी करना चाहते हैं या जिनकी हाल ही में शादी हुई है।

119. यह विवाद से परे है कि अंतर-जातीय और अंतरधार्मिक संबंधों में जोड़े ऐतिहासिक रूप से अपने संघों को संपन्न करते समय भारी कठिनाई से जूझने और संघर्ष करना जारी रखते हैं। जैसा कि पिछले प्रस्तर में चर्चा से स्पष्ट है, समाज का एक बड़ा वर्ग इस तरह के विवाहों का घोर विरोध करता था और है। विरोध-स्थिति, कम से कम आंशिक रूप से, एक विश्वास से उपजी है कि एक विवाह में एक ही धर्म या जाति के दो इंडि-विडुअल शामिल होने चाहिए। सम-संबंध ने असामान्य विवाहों के विरोध के बावजूद एस.एम.ए. को अधिनियमित करने का विकल्प चुना और ऐसे जोड़ों के समुदायों से निरंतर शत्रुता के बावजूद एस.एम.ए. को निरस्त करने या अन्यथा व्यक्तिगत



कानूनों के तहत अंतर-जातीय विवाह के उत्सव को बाहर करने का विकल्प नहीं चुना है। संसद ने संभवतः ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत है कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग समुदाय के अनुमोदन पर निर्भर नहीं है। इसी तरह, इस न्यायालय ने व्यक्तियों और जोड़ों के परिवारों के काफी विरोध के बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा करके संवैधानिक मानव-तिथि का पालन किया है। लोकतंत्र में, कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों में निहित हैं। यदि अधिकारों का प्रयोग हर किसी पर निर्भर था या, कम से कम इस तरह के अभ्यास को मंजूरी देने वाले समुदाय का एक बड़ा हिस्सा था, तो हम एक संवैधानिक लोकतंत्र-जाति का नुकसान कर रहे होंगे। संविधान में भारतीयों को संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से पहले उनके लिए वैधता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है।

40. यह न्यायालय पहले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुबंधित अंतरधार्मिक विवाह पर विचार कर चुका है और इस न्यायालय द्वारा मायरा @ वैष्णवी विलास शिरशिकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2021 की रिट-सी संख्या-14806 के मामले में 18.11.2021 को निर्णय दिया गया था और यह देखा गया था कि विवाह के भीतर या बाहर के साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में निहित है। यह भी देखा गया कि अधिनियम, 2021 अपने आप में अंतरधार्मिक विवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है। मायरा (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"I. विश्लेषण और निष्कर्ष

100. सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ अन्य संवैधानिक न्यायालयों ने समय-समय पर यह महसूस किया है कि तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे समाज में, संविधान की स्थिर न्यायिक व्याख्या संविधान की भावना को कमजोर कर देगी।

101. निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा इस देश के नागरिकों को गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। एक नागरिक को अन्य मामलों के साथ-साथ अपने परिवार, अपने परिवार, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, बच्चे पैदा करने और शिक्षा की गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है।



102. परिवार या समुदाय या कबीले या राज्य या कार्यपालिका की सहमति आवश्यक नहीं है, एक बार जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत हो जाते हैं जो वैध और कानूनी है। उनकी सहमति को अनुग्रह और गरिमा के साथ पवित्रता से दायर की दी जानी चाहिए। विवाह अधिकारी/रजिस्ट्रार विधिवत संपन्न विवाह को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता है, और/या, जिला प्राधिकरण के रूपांतरण अनुमोदन पर जोर नहीं दे सकता है।

103. विवाह का तथ्य और विवाह का पंजीकरण पूरी तरह से अलग और अलग है। पंजीकरण केवल पक्षों के बीच विवाह के तथ्य का प्रमाण देता है, जबकि, विवाह की वैधता, चाहे वह शून्य हो या शून्यकरणीय हो, पीड़ित पक्ष के लिए नामित मंच/न्यायालय के समक्ष कानून के अनुसार समझौता करना है।

104. न्यायालय का कर्तव्य अधिकार को बनाए रखना है और अधिकार के क्षेत्र को कम नहीं करना है जब तक कि कानून का वैध अधिकार न हो। साथी का चुनाव, चाहे विवाह के भीतर हो या बाहर, प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य डोमेन के भीतर होता है। विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के एक मुख्य क्षेत्र के भीतर होती है, जो अनुल्लंघनीय है। जीवन साथी चुनने का व्यक्ति का पूर्ण अधिकार आस्था के मामलों से कम से कम प्रभावित नहीं होता है।

105. एक जीवित साधन के रूप में संविधान, जो भारतीय समाज के लिए शाश्वत मूल्यों का प्रतिपादन करता है, इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन रखता है। संविधान को परिवर्तन से परे कठोर बनाने के लिए पत्थर में नहीं डाला गया है। संविधान के लिए बुनियादी विशेषताएं तरल रूप से अनुकूल हैं और बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का सटीक रूप से जवाब देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उन सिद्धांतों को लागू करने की अनुमति मिल सके जिन पर इसकी स्थापना की गई है, ताकि वे अपने समय की कठिन समस्याओं के अभिनव समाधान ढूंढ सकें। ऐसा करने में, हमें समान रूप से समझना चाहिए कि हमारे समाधानों को लगातार री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। संविधान व्याकरण की तुलना में दर्शन के दायरे में है। 1950 के बाद से 70 वर्षों में संविधान में बदलाव (100 से अधिक संशोधन) हुए हैं, जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए



बदलते सामाजिक परिवेश के अनुरूप है।

106. कानून का मूल्यांकन उसके उद्देश्य के संदर्भ में नहीं बल्कि निष्पक्षता और तर्कसंगतता के परीक्षण के आधार पर मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। गैरकानूनी रूपांतरण अधिनियम, 2021, अपने आप में, अंतरधार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि, विवाह रजिस्ट्रार/अधिकारी के पास विवाह के पंजीकरण को रोकने की शक्ति का अभाव है, केवल इस कारण से कि पक्षों ने जिला प्राधिकरण से धर्मांतरण की आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की है। इस तरह की स्वीकृति निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। यदि अन्यथा व्याख्या की जाती है तो अधिनियम तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी को पूरा नहीं करेगा, और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के मस्टर को पारित करने में विफल रहेगा।

जे - राहत

107. रिट याचिकाओं को निम्नलिखित आदेश पारित करके अनुमति दी जाती है:

(i) राज्य के प्रतिपक्षियों और निजी प्रतिपक्षियों को पुरुष और महिला के रूप में रहने के लिए याचिकाकर्ताओं के जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है;

(ii) संबंधित जिलों के पुलिस प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और मांग किए जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे;

(iii) संबंधित जिलों के विवाह रजिस्ट्रार/अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे धर्म परिवर्तन के संबंध में सक्षम जिला प्राधिकारी के अनुमोदन पर जोर दिए बिना/प्रतीक्षा किए बिना, याचिकाकर्ताओं के विवाह का पंजीकरण तत्काल करें;

(iv) धोखाधड़ी और गलत बयानी की स्थिति में, पीड़ित पक्ष के लिए कानून का सहारा लेने के लिए खुला होगा, दोनों - आपराधिक और नागरिक, सक्षम मंच के समक्ष विवाह को रद्द करना;

(v) भारत सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार अनुच्छेद 44 के अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए एक समिति/आयोग के गठन पर विचार करेगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) राज्य सरकार इस आदेश का अनुपालन करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए विवाह रजिस्ट्रार/अधिकारी, जिला प्राधिकरण को उपयुक्त सरकारी आदेश जारी करेगी;

(vii) आदेश से प्रभावित होने की स्थिति में इस आदेश में संशोधन/वापस लेने की मांग करने के लिए निजी प्रतिपक्षीगण के लिए खुला होगा;

(ix) इस न्यायालय के महापंजीयक को निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति निम्नलिखित को प्रदान करें-

(क) न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

41. इस न्यायालय ने आकांक्षा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य के मामले में, रिट-सी संख्या-35171 वर्ष 2025 के मामले में, 17.12.2025 को फैसला सुनाया, एक ही धर्म के याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की, जो वयस्क थे और उन्होंने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया था। आकांक्षा (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर-यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"46. एक बार जब एक व्यक्ति, जो एक वयस्क है, ने अपने साथी को चुन लिया है, तो यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर आपत्ति करने और बाधा उत्पन्न करने के लिए अनुमत नहीं है। प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है, जो उस पर लगाए गए संवैधानिक दायित्वों के अनुसार है। मानव जीवन के अधिकार को बहुत अधिक उच्च स्तर पर माना जाना चाहिए, भले ही कोई नागरिक नाबालिग या बड़ा, विवाहित या अविवाहित हो। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने विवाह नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक का मौलिक अधिकार बहुत अधिक ऊंचे पायदान पर खड़ा है। पवित्र होने के नाते, संवैधानिक योजना के तहत इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही विवाह संपन्न हो या यहां तक कि पक्षों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



47. यहां याचिकाकर्ता, जो वयस्क हैं, ने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया है और यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे अपने फैसले पर उनका न्याय करें। यदि याचिकाकर्ताओं ने यहां कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समन्वय पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों के उचित सम्मान के साथ, जिन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सुरक्षा से वंचित कर दिया है, यह न्यायालय उसी दृष्टिकोण को अपनाने में असमर्थ है।

48. यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह (उपरोक्त), एस. खुशबू (उपरोक्त), इंद्रा सरमा (उपरोक्त) और शफीन जहां (उपरोक्त) के मामले में और हमारे सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अन्य निर्णयों में व्याख्या की है, कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अनिवार्य है।

49. न्यायालय की राय में, एक व्यक्ति, जिसने बहुमत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, अपने कल्याण को समझने में सक्षम है और इसलिए, उसे जहां चाहें वहां जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वह किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता है।

51. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता शांति से एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किया गया एक मौलिक जीवन है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

52. यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/एसएसपी/एसपी से संपर्क



करेंगे और पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता बड़े हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि याचिकाकर्ता शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि किसी भी अपराध के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। यदि उनके पास उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और या अनपढ़/अर्ध-साक्षर हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की को उनकी सही उम्र को सत्यापित करने के लिए अस्थि-पंजर परीक्षण करा सकता है और वह कानून के तहत अनुमत अन्य प्रक्रिया का भी पालन कर सकता है।

53. तदनुसार, पूर्वोक्त रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

42. इस न्यायालय को इस मामले में भी अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं दिखता है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार कानून सभी के लिए समान है और यदि एक ही धर्म के दो व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह सकते हैं, तो अलग-अलग धर्म वाले अन्य व्यक्ति भी लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह सकते हैं।

43. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। संदर्भ के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"14. विधि के समक्ष समानता--राज्य, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

15. धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध - (1)
राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।



(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्तों के अधीन नहीं होगा?

(क) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक विश्राम के स्थानों का उपयोग जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से अनुरक्षित हो या आम जनता के उपयोग के लिए समपत हो।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से विदा नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में दी कोई बात राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से विबाधा नहीं करेगी।

(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में दी कोई बात राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्नयन के लिए कानून द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से विवश नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त।

(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में दी कोई बात राज्य को यह करने से नहीं रोकेगा;

(क) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध; तथा

(ख) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी आर्थिक रूप से



कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थाओं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण के मामले में प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों की मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यक्षीन होगा।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक हानि के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जाए।

44. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने शफीन जहां (उपरोक्त) का फैसला सुनाते हुए कहा है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली या विश्वास को आगे बढ़ाने की क्षमता की रक्षा करता है जिसका वह पालन करना चाहता है। शफीन झाना (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"17. बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर विचार करते हुए, विवाह को शून्य और शून्य घोषित करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति से अधिक है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में, संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। यह दूसरा पहलू है जिसकी ओर अब हम मुड़ते हैं।

18. हादिया और शफीन जहां वयस्क हैं। मुस्लिम कानून के तहत शादी या निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम कानून वयस्कों के अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार को मान्यता देता है। वैध मुस्लिम विवाह के लिए शर्तें हैं:

(i) दोनों व्यक्तियों को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए;

(ii) दोनों यौवन की आयु के होने चाहिए;

(iii) एक प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए और दो गवाह उपस्थित होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहिए;

(iv) दहेज और मेहर; तथा

(v) रिश्ते की निषिद्ध डिग्री का अभाव।

19. एक विवाह को पक्षकारों के इशारे पर, कानून की एक सक्षम अदालत द्वारा भंग किया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति कानून के माध्यम से प्रदान की जाती है या, जैसा भी मामला हो, रीति-रिवाज के अनुसार। वैवाहिक स्थिति से वंचित करना गंभीर महत्व का मामला है और यह सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को विवाह को रद्द करने की राह पर नहीं चलना चाहिए था। संविधान उस स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मान्यता देता है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। इसमें उन पहलुओं पर निर्णय लेने की क्षमता शामिल है जो किसी के व्यक्तित्व और पहचान को परिभाषित करते हैं। विवाह के भीतर या बाहर साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में होता है। विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के एक मुख्य क्षेत्र के भीतर होती है, जो अनुल्लंघनीय है। जीवन साथी चुनने का व्यक्ति का पूर्ण अधिकार आस्था के मामलों से कम से कम प्रभावित नहीं होता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है। वास्तव में विवाह के मामलों में विश्वास और विश्वास के विकल्प एक ऐसे क्षेत्र के भीतर निहित हैं जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च है। कानून वैध विवाह के लिए शर्तें निर्धारित करता है। यह रिश्ते टूटने पर उपाय प्रदान करता है। न तो राज्य और न ही कानून भागीदारों की पसंद को निर्देशित कर सकता है या इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकता है। वे संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार हैं। यह तय करने में कि क्या शफीन जहां हादिया की शादी के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, उच्च न्यायालय ने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है। हमारी पसंद का सम्मान किया जाता है क्योंकि वे हमारे हैं। अंतरंग व्यक्तिगत निर्णयों के लिए सामाजिक अनुमोदन उन्हें पहचानने का आधार नहीं है। दरअसल, संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शकों को अस्वीकार करने से बचाता है।

20. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 16 मानव स्वतंत्रता की घटना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में विवाह के मौलिक महत्व को रेखांकित करता है:

"अनुच्छेद 16.

(1) पूरी उम्र के पुरुषों और महिलाओं को, जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण बिना किसी सीमा के, शादी करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के दौरान, विवाह के दौरान और उसके विघटन के समय समान अधिकारों के हकदार हैं।

(2) विवाह केवल इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।

(3) परिवार समाज की स्वाभाविक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार है।

21. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। संविधान जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार को एक ऐसे कानून के अलावा नहीं छीना जा सकता है जो ठोस और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। स्वतंत्रता के लिए आंतरिक है जिसे संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति की खुशी की खोज के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। विश्वास और विश्वास के मामले, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है कि क्या संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में हैं। संविधान विश्वासियों के साथ-साथ अज्ञेयवादियों के लिए भी मौजूद है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली या विश्वास को आगे बढ़ाने की क्षमता की रक्षा करता है जिसका वह पालन करना चाहता है। पोशाक और भोजन के मामले, विचारों और विचारधाराओं के, प्यार और साझेदारी के मामले पहचान के केंद्रीय पहलुओं के भीतर हैं। कानून एक वैध विवाह की शर्तों को (संवैधानिक अनुपालन के अधीन) विनियमित कर सकता है, क्योंकि यह उन स्थितियों को विनियमित कर सकता है जिनमें वैवाहिक बंधन को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। ये उपाय विवाह के पक्षों के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि वे ही सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं कि क्या वे 06-12-2024 (पृष्ठ 25 वर्ष 27) www.manupatra.com लीगल ऑब्जर्वर ट्रस्ट को एक-दूसरे को वैवाहिक बंधन में स्वीकार करना चाहिए या उस रिश्ते में जारी रखना चाहिए। भागीदारों की हमारी पसंद को निर्धारित करने में समाज की कोई भूमिका नहीं है।



22. केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ MANU/SC/1044/2017: 2017 (10) SCC

1 में, इस न्यायालय ने नौ न्यायाधीशों के एक निर्णय में माना कि किसी के जीवन के करीब मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता मानव व्यक्तित्व का एक अनुल्लंघनीय पहलू है:

"व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन के लिए चिंता के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उस पर विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं।

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कॉमन कॉज (ए रेजिड. सोसाइटी) बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) संख्या-215 वर्ष 2025 में, अवधारित किया कि:

"व्यक्तियों के रूप में हमारी स्वायत्तता यह तय करने की क्षमता पर आधारित है: क्या पहनना है और कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है और जो भोजन हम साझा करते हैं, कब बोलना है और हम क्या बोलते हैं, विश्वास करने या न करने के अधिकार पर, किससे प्यार करना है और किसके साथ साझेदारी करनी है, और हमारे दैनिक जीवन के परिणाम और विस्तार के असंख्य मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

इसलिए, संविधान की ताकत इस गारंटी में निहित है कि यह प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास विवाह के भीतर या बाहर अंतरंगता साझा करने के लिए साथी की पसंद का निर्धारण करने में एक संरक्षित अधिकार होगा।

23. उच्च न्यायालय ने, प्रस्तुत मामले में, एक ऐसे क्षेत्र पर कदम रखा है जो एक संवैधानिक न्यायालय के लिए सीमा से बाहर होना चाहिए। उच्च न्यायालय के विचारों ने महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित एक निजी स्थान का अतिक्रमण किया है, जिसमें न तो कानून और न ही न्यायाधीश घुसपैठ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का मानना था कि चौबीस साल की उम्र में हादिया कमजोर है, जिसका कई तरह से शोषण किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को खो दिया है कि वह एक वयस्क



है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार की हकदार है कि वह अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत कर सके। इस मामले में हस्तक्षेप करने में इस न्यायालय की चिंता न्याय के हानि के बारे में उतनी ही है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय भी उतना ही पितृत्व के बारे में भी है जो अपील में दिए गए फैसले में परिलक्षित संवैधानिक व्याख्या के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। उच्च न्यायालयें, जब वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, तो पितृसत्ता उन व्यक्तियों के मामले में ऐसा करती है जो स्वतंत्र इच्छा का दावा करने में असमर्थ हैं जैसे कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति। उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग वैवाहिक बंधन के लिए भागीदारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह निर्णय विशेष रूप से स्वयं व्यक्तियों पर निर्भर करता है। न तो राज्य और न ही समाज उस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है। हमारे संविधान की ताकत हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को स्वीकार करने में निहित है। विवाह की अंतरंगता, जिसमें व्यक्ति शादी करने या न करने और किससे शादी करने के विकल्प चुनते हैं, राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में अदालतों को इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए। हमारे समाज का सामंजस्य और स्थिरता हमारी समन्वयात्मक संस्कृति पर निर्भर करती है। संविधान इसकी रक्षा करता है। अदालतें एक राष्ट्र के रूप में हमारे बहुलवाद और विविधता को बनाए रखने के मार्ग से न हटने के लिए बाध्य हैं।

24. ऐसे मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप का स्वतंत्रता के प्रयोग पर गंभीर रूप से भयावह प्रभाव पड़ता है। दूसरों को प्रतिशोध के डर से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पसंद का स्वतंत्र अभ्यास हो सकता है। दूसरों पर द्रुतशीतन प्रभाव उन्हें अपनी स्वतंत्रता का दावा करने से रोकने के लिए एक हानिकारक प्रवृत्ति है। राज्य शक्ति के कठोर प्रयोग से जुड़े सार्वजनिक तमाशे उसी परिवेश में अन्य लोगों द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग को रोकते हैं। स्वतंत्रता के लिए कुछ भी इतना विनाशकारी नहीं हो सकता है। डर स्वतंत्रता को चुप करा देता है।

45. यह न्यायालय यह अभिलक्षित करता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में युवा युगल संरक्षण की प्रार्थना लेकर उपस्थित हो रहे



हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 24328 वर्ष 2019 (सुमन अहिरवार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, (2018)7 एससीसी 192 में प्रदत्त निर्णय का संज्ञान लेते हुए, राज्य के प्राधिकारियों को निर्देशित किया था कि ऐसे प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए तथा आवश्यक दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएँ। उक्त निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-1/2019/591 क-रिट/छ-पु.-3-2019-2(344)पी/2019 दिनांक 31.08.2019 जारी किया गया, जिसके माध्यम से विवाह अथवा किसी भी सहमति-आधारित संबंध के कारण धमकी का सामना कर रहे युगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निवारक, उपचारात्मक तथा दण्डात्मक उपाय निर्धारित किए गए।

46. उक्त सरकारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी प्रत्येक मामले में खतरे की धारणा का आकलन करेंगे, सुरक्षित आवास सहित आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेंगे और स्थिति की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि खाप पंचायतों से जुड़े मामलों या सम्मान आधारित धमकियों को गंभीर मामलों के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि पारिवारिक विरोध के अन्य मामलों में भी, अधिकारी जोखिम का मूल्यांकन करने और उचित राहत प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। इन निर्देशों का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई दंडनीय बना दिया गया है। दिनांक 31.8.2019 के उपरोक्त सरकारी आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

(3) 2- उपचारात्मक उपाय:-

(ए) ...

(बी) ...

(सी) इसके अतिरिक्त कपल/पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें उसी जिले में उनकी सुरक्षा व भय को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखा जाये।

(i) ऐसे युवा अविवाहित कपल (जोड़े) जिनके सम्बन्धों को परिवार द्वारा अथवा स्थानीय खाप द्वारा विरोध किया जाता है।



(ii) ऐसे युवक विवाहित (युवक/युवतियाँ) जो अन्तर्जातीय व अन्तरधर्मीय विवाह से सम्बन्धित हैं उन्हें सुरक्षित रखने हेतु क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरक्षित घरों में रखने की व्यवस्था की जाये।

(डी) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे युगल अथवा परिवार के सदस्यों के जीवन-भय के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों पर संवेदनशीलता बरती जाये। पहले यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे अविवाहित युवक/युवतियाँ जो यदि वयस्क हों तो उन्हें विवाह हेतु सहयोग प्रदान करते हुए विवाह पंजीकरण में सहयोग प्रदान किया जाये। विवाह के पश्चात यदि वे इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन्हें न्यूनतम दर पर 01 माह के लिये सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाये, किन्तु यह 01 वर्ष से अधिक की अवधि से अधिक नहीं होगी जो उनके जीवन-भय की समय सीमा पर आधारित होगी।

(ई) ऐसे अविवाहित युवक/युवतियाँ अथवा युवा विवाहित जोड़ों अथवा स्वतन्त्र स्रोत से शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच करायी जाय कि क्या उनके द्वारा या स्थानीय समुदाय या खाप द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। तब जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं जीवन-भय की समस्या के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच करायी जायेगी और जाँच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 01 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जायेगी।

47. सुविधा के लिए, दिनांक 31.8.2019 के सरकारी आदेश के उपर्युक्त उद्धरण का अंग्रेजी अनुवादित संस्करण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"3(2) उपचारात्मक उपाय

(क) ...

(ख) ...

(ग) इसके अतिरिक्त, दंपति/परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले के भीतर एक सुरक्षित घर में रखा जाना चाहिए।

(i) युवा अविवाहित जोड़े जिनके रिश्ते का उनके परिवारों या स्थानीय खाप द्वारा विरोध किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) ऐसे युवा विवाहित (लड़कियों/लड़के) जो अंतर-जातीय या अंतर-धामक विवाह से संबंधित हैं, उन्हें क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की देखरेख और निर्देशों के अधीन सुरक्षित घरों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को ऐसे दंपति/परिवार को दी गई धमकियों से संबंधित शिकायत पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। पहले यह पता लगाया जाना चाहिए कि ऐसे अविवाहित जोड़ों, यदि वे वयस्क हैं, तो उन्हें उनकी शादी की पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। शादी के बाद, यदि दंपति चाहें तो उन्हें एक महीने की अवधि के लिए एक सुरक्षित घर में मामूली शुल्क के भुगतान पर आवास प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं, जो मामले के आधार पर उनके खतरे के आकलन पर निर्भर करता है।

(ङ) अविवाहित दंपति अथवा युवा विवाहित जोड़े से प्राप्त शिकायत अथवा किसी स्वतंत्र स्रोत से यह सूचना प्राप्त होने पर कि उनके/स्थानीय समुदाय/खाप द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, के संबंध में जांच की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मामले की गंभीरता और खतरे की धारणा के संबंध में प्रारंभिक जांच करेंगे और वह एक सप्ताह के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने अपने निर्णय के एक अंश में माना है कि लिव-इन संबंध किसी भी कानून के तहत न तो निषिद्ध है और न ही दंडनीय है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 और अधिनियम, 2021 पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इंटरफेथ कपल का लिव-इन रिलेशनशिप एक अपराध है। यदि कोई अपराध किया गया होता, तो इसकी सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, 2021 की धारा 4 के अनुसार दी गई होती। याचिकाकर्ताओं के लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में आज तक कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरे, यह न्यायालय यह पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं को लिव-इन रिलेशनशिप में रखकर कोई अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर यह न्यायालय केवल याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के मुद्दे की जांच कर रहा है, जैसा कि याचिका में वर्णित कारणों/परिस्थितियों के लिए है। यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

49. मुद्दा जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करने के मौलिक अधिकार से वंचित करना है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार बहुत अधिक ऊंचाई पर खड़ा है। संवैधानिक योजना के तहत पवित्र होने के कारण इसे अमान्य या शून्य विवाह के संपन्न होने या यहां तक कि पक्षों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति की परवाह किए बिना संरक्षित किया जाना चाहिए।

50. प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना उस पर डाले गए संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह परम कर्तव्य है। मानव जीवन के अधिकार को बहुत अधिक उच्च पायदान पर माना जाना चाहिए, भले ही नागरिक की धार्मिक आस्था कुछ भी हो। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक अंतर-धार्मिक संबंध में रह रहे हैं, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

51. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ **अनुमति** दी जाती है:

(i) याचिकाकर्ता निजी प्रतिपक्षियों या उनके सहयोगियों द्वारा कोई नुकसान पहुंचाए जाने की स्थिति में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं के मामले और उम्र की जांच करेंगे और यदि उन्हें याचिकाकर्ताओं के आरोपों में कोई दम मिलता है, तो वे याचिकाकर्ताओं के जीवन, अंग और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार कार्य करेंगे।

(ii) यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध या किसी कपटपूर्ण तरीके से, बल, जबरदस्ती, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी के अभ्यास द्वारा अपना धर्म बदलने का प्रयास करता है तो याचिकाकर्ता रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

(iii) दिनांक 31.08.2019 के उपरोक्त सरकारी आदेश में निहित निर्देश सभी संबंधित



अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं और इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(iv) यह आदेश, यदि कोई हो, पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष लंबित जांच, यदि कोई हो, के रास्ते में नहीं आएगा।

52. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

53. इन मामलों से अलग होने से पहले, मैं श्री श्वेताश्व अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री सुबीर लाल और श्री शाश्वत गुहा द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए अपना आभार और प्रशंसा व्यक्त करूंगा।

54. उपरोक्त नामित राज्य परामर्शदाताओं द्वारा की गई कड़ी मेहनत के साथ-साथ तर्क भी सराहनीय हैं।

55. मैं अपने रिसर्च एसोसिएट सुश्री प्रियांशी हिरवानी की सराहना करना चाहता हूं, जो इस निर्णय का मसौदा तैयार करने में अनुसंधान में उनकी निपुणता और उत्कृष्ट सहायता के लिए हैं।

56. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की सही उम्र का फैसला नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

57. चूंकि इस याचिका का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर (इन लिमिने) पर ही किया जा रहा है, अतः यदि यह आदेश तथ्यों के दमन अथवा छिपाव, या मिथ्या अभिकथनों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश को प्रत्याहृत (रि कॉल) किए जाने हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक: 23.02.2026 / ए पी पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)